RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

दैनिक क्रांति समय

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 285, शनिवार, 12 अक्टुबर, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्टर्ड ऑफिसः- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दूसरी अनौपचारिक मुलाकातः पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग ने पंच रथ स्थल पर साथ में नारियल पानी का चखा स्वाद

प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल वेशभूषा में किया जिनपिंग का स्वागत, महाबलीपुरम के ऐतिहासिक स्थल देखे

- भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच 40 मिनट तक वन टू वन मीटिंग

चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को महाबलीपुरम पहुंचे। मोदी यहां चीन के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पारंपरिक तमिल वेशभूषा में पहुंचे। उन्होंने मामल्लपुरम में जिनपिंग को अर्जुन तपस्या स्थली और तट मंदिर के दर्शन कराए और इन स्थलों का महत्व समझाया। इसके बाद दोनों ने पंच रथ स्थल पर नारियल पानी पिया और अनौपचारिक बातचीत की शुरुआत की। इससे पहले जिनपिंग का चेन्नई एयरपोर्ट पर भी स्वागत किया गया। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का कार्यक्रम करीब 6 घंटे तक चला। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच 40 मिनट तक वन टू वन मीटिंग की। जिनपिंग के चेन्नई पहुंचने पर मोदी ने अंग्रेजी, तमिल और मेंडेरिन में ट्वीट किया- भारत में आपका स्वागत है राष्ट्रपति जिनपिंग।

एयरपोर्ट को फूलों से सजाया

जिनपिंग के स्वागत की विशेष तैयारियां की गई थीं। चेन्नई एयरपोर्ट को पारंपरिक रूप से केले के पत्तों, फल-फूल मालाओं के साथ सजाया गया था। 2000 स्कूली छात्र जिनपिंग का मुखौटा पहनकर अंग्रेजी के शब्द वेलकम की मुद्रा में पहुंचे। एयरपोर्ट से जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी होटल जाएंगे। वहां खाना खाने के बाद शाम करीब 5 बजे जिनिपंग 60 किमी दूर महाबलीपुरम पहुंचेंगे। वहां वह विश्व विरासत स्थल में शामिल शोर मंदिर, 7वीं सदी का अर्जुन का तपस्या स्मारक, पल्लव वंश द्वारा बनाए गए पंच रथ मंदिर देखेंगे। वहां से दोनों नेता डिनर के लिए जाएंगे। शनिवार सुबह प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद मोदी और जिनपिंग भोजन करेंगे। दोपहर में जिनपिंग चीन लौट जाएंगे।

मोदी ने कहा- भारत-चीन के रिश्ते मजबूत होंगे

मोदी पहले ही चेन्नई पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात से भारत और चीन के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शुक्रवार और शनिवार को दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। साथ ही चेन्नई के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम (मामल्लपुरम) में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चेन्नई से महाबलीपुरम तक 5 हजार जवान तैनात किए गए हैं। रास्तों और कार्यक्रम स्थल पर 800 सीसीटीवी कैमरे लगे लगाए गए हैं। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने समुद्र तट से कुछ दूरी पर युद्धपोत तैनात किए हैं।

आतंकवाद, टेरर फंडिंग पर चर्चा संभव

जिनपिंग के साथ चीन के विदेश मंत्री और पोलित ब्यूरो के सदस्य भी भारत आएंगे। इस बैठक के लिए कोई एजेंडा तय नहीं है, लेकिन भारत-प्रशांत क्षेत्र, सीमा विवाद, आतंकवाद, कारोबारी असंतुलन, टेरर फंडिंग के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान कोई समझौता और एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, लेकिन मोदी-जिनपिंग की ओर से साझा बयान जारी हो सकता है। मोदी पिछले साल अप्रैल में पहली अनौपचारिक बैठक के लिए चीन के वुहान गए थे। दोनों नेता बैंकॉक में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने जा रहे आसियान समिट में भी मिलेंगे।

चीन का महाबलीपुरम से है ऐतिहासिक संबंध

तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी किनारे स्थित महाबलीपुरम शहर चेन्नई से करीब 60 किमी दूर है। पुरातत्त्वविद् एस राजावेलु के मुताबिक, इसकी स्थापना धार्मिक उद्देश्यों से 7वीं सदी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने कराई थी। नरसिंह ने मामल्ल की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। यहां शोध के दौरान चीन, फारस और रोम के प्राचीन सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। प्राचीन बंदरगाह वाले महाबलीपुरम का करीब 2000 साल पहले चीन के साथ खास संबंध था। पुरातत्त्वविद राजावेलू बताते हैं कि कि यहां बरामद हुए पहली और दूसरी सदी के मिट्टी के बर्तन हमें चीन के समुद्री व्यापार की जानकारी देते हैं। पल्लव शासन के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग कांचीपुरम आए थे। पल्लव शासकों ने चीन में अपने दूत भेजे थे।

यात्रा से पहले चीन ने कश्मीर मुद्दे पर अपना रुख बदला

जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले चीन ने मंगलवार को कश्मीर मसले पर अपना रुख बदल लिया था।

मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि इस मसले को द्विपक्षीय तरीके से हल किया जाना चाहिए। इससे पहले चीन ने कश्मीर मुद्दे पर में संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक हल निकाले जाने की बात कही थी। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दौरे के दौरान चीन ने कहा था कि कश्मीर के हालात पर उसकी नजर है।

चुनाव-प्रचारः प्रदीप रातुसरिया को जिताएं तभी सिरसा की होगी सत्ता में भागीदारीः मनोहर लाल

सिरसा, हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र से यदि प्रदीप रातुसरिया को जीत हासिल होती है तो सिरसावासियों की सत्ता में सीधे भागेदारी होगी। वे वीरवार देर शाम को नेहरू पार्क के रामलीला मैदान में पहुंची सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव और शहर से आई जनता को संबोधित कर रहे थे। यहां पहुंचने पर जिलाध्यक्ष यतिंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया और पांचों सीटें जीतकर मनोहरलाल की झोली में डालने का वादा किया। जनसैलाब में युवाओं और महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी थी। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि सिरसा की सभी समस्याओं से वे पूरी तरह वाकिफ हैं और यहां की सबसे बड़ी समस्या नशे को जड़मूल से समाप्त करने के लिए हरियाणा राज्य की पहल पर 8 राज्यों ने मिलकर एक कार्य योजना तैयार की है जिसका मुख्यालय पंचकुला में बनाया गया है। नई सरकार का गठन होने के बाद सिरसा जिला के सीमावर्ती इलाकों में नशे को खत्म करने के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रातुसरिया के पिता महावीर रातुसरिया ने लंबे समय तक जनसंघ और भाजपा की सेवा की और इस शुद्ध सात्विक परिवार से संबंध रखने वाले प्रदीप रातुसरिया को यहां की जनता की मांग पर उम्मीदवार बनाया गया है। यहां के लोगों ने लोकसभा चुनावों में 41 हजार मतों से सुनीता दुग्गल को लीड दी थी और अब ऐसा अनुमान है

कि 51 वर्षीय उम्मीदवार प्रदीप रातुसरिया के लिए यह लीड 51 हजार तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने भारत माता के जयकारों से अपना संबोधन आरंभ किया और जैसे ही उन्होंने उम्मीदवार के रूप में प्रदीप रातुसरिया का नाम लेकर अपने पास बुलाया तो जैनसलाब ने तालियों से उनका जोरदार स्वागत किया तथा रातुसरिया जिंदाबाद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पांच साल में हरियाणा के ढाई करोड़ के अपने परिवार की निष्काम भाव से सेवा की है और पीछे मुडकर नहीं देखा। हालांकि सिरसा जिला में भाजपा का एक भी विधायक नहीं था लेकिन सरकार की पहली बैठक में हर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और इसकी गवाही के लिए मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद सिरसा के निवर्तमान विधायक मक्खनलाल से हामी भरवाई। उसके बाद वे लगातार प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अनेक बार गए और यहां पर जब भी आए यहां के लोगों की मांग के अनुसार विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया। इस अवसर पर सिरसा लोकसभा प्रभारी श्रीनिवास गोयल, सांसद सुनीता दुग्गल, मक्खनलाल सिंगला, जगदीश चोपड़ा, सिरसा प्रभारी देवकुमार शर्मा, पदम जैन, डॉ. अमर सिंह सिद्धु, भूपेश मेहता, रेणू शर्मा, रतनलाल बामनिया, हनुमान कुंडू, नीरज बंसल, तरूण गुलाटी, मनीष सिंगला, अमन चोपड़ा, प्रवक्ता कपिल सोनी, कृष्ण मेहता, सूरतगढ़ के विधायक अशोक नागपाल, श्याम बजाज, राजबीर गोदारा, मुकेश लाखलान, सुनील बामनिया, सुमन बामनिया, सुमन शर्मा, राजेंद्र जिंदल, राजेंद्र रिणवा विस्तारक, वीर शांतिस्वरूप, भावना शर्मा, सुरेश पंवार, तरसेम सामां, नंदलाल भट्टूवाला, सुखविंद्र बराड़, रामकिशन तंवर, भोजराज गुर्जर, आशा जैन, पार्षद कौशल्या वर्मा, नारायणपाल, सुनील बहल, दीपक वाल्मीकि, जगत कक्कड़, विरेंद्र तिन्ना, विनोद स्वामी, विक्रम चानणा, नरेश सैनी सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

ईमानदारी की सरकार में ही किसी हलके में 800 करोड़ विकास पर लग सकता हैः योगी आदित्यनाथ

पंजकुला, हरियाणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी लतिका शर्मा के समर्थन में प्रचार करने के लिए कालका पहुंचे। शुक्रवार को कालका सब्जी मंडी ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि ईमानदारी की सरकार में ही किसी हलके में 800 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर लग सकता है। जबकि इससे पहले कई बार कालका और हरियाणा में कांग्रेस को शासन का नेतृत्व प्राप्त हुआ परन्तु उन्होंने कभी भी कालका और पचंकूला में विकास को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस शासन में तो जमीन घोटाले, 2जी या फिर दामाद जी ने तो गुरुग्राम से लेकर पचंकूला तक कोई जमीन नहीं छोड़ी थी, जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित न किए हों। जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो कांग्रेसी नेता उनकी जय-जयकार के नारे लगाते हैं। इसलिए वो भारत माता की जय नहीं करते। हरियाणा में अगर ईमानदारी व अरबों के विकास करवाने वाली वही सरकार चाहिए तो कालका से लतिका शर्मा और पचंकूला से ज्ञानचंद गुप्ता को भारी मतों से जिताना होगा। इस मौके पर केन्द्रीय राज्य मंत्री रत्नलाल कटारिया, कालका प्रत्याशी लतिका शर्मा, पचंकूला प्रत्याशी ज्ञान चंद गुप्ता, विधानसभा प्रभारी श्यामलाल बसंल, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, ज़िला अध्यक्ष दीपक शर्मा, ज़िला उपाध्यक्ष संजीव कौशल , ज़िला महामंत्री विरेन्द्र राणा व हरेंद्र मलिक, रूबी भगत सिंह, हर्ष कुमार, कुलभूषण गोयल, पवन कुमारी, तरसेम गुप्ता, फतेह सिंह, ईन्द्र कुमार, सुनील धीमान, रितु सिंगला, कृष्ण ढुल, बालयोगी आदि समेत हजारो कार्यकर्ता मौजूद थे।

हरियाणा में कांग्रेस के साथ हर वर्गः कुमारी शैलजा

चंडीगढ़ हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का 'संकल्प पत्र' जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार पूरे पांच साल तक जमीनी हकीकत से कटी रही। मुख्यमंत्री ने भाजपा की ओऱ से हरियाणा की जनता से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। जबकि कांग्रेस हमेशा से वचन की पक्की रही है। इस बार संकल्प पत्र में शामिल वायदों को सरकार में आते ही पहली कलम से पूरा करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। पार्टी ने दावा किया

है कि उसका घोषणा पत्र हर वर्ग के लिए कल्याणकारी होगा। इसमें किसान, कर्मचारी, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बुजुर्गों, व्यापारियों, उद्योगपतियों व आम जनता का विशेष ख्याल रखा गया है। बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस भत्ता देगी। कांग्रेस के 'संकल्प पत्र' में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने औऱ निजी संस्थानों में भी महिला आरक्षण लागू करने का भरोसा दिया गया है। रोडवेज में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। महिलाओं के लिए अलग बसें होंगी, जिनमें महिला चालक और परिचालक होंगी। गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म तक 3,500 रुपये हर माह दिए जाएंगे। उसके बाद पांच साल तक 5 हजार दिए जाएंगे। बीपीएल महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये चूल्हा खर्च दिया जाएगा।

लुधियाना में करवाया मोटरसाइकिल स्टंट शो

चंडीगढ/लुधियाना। पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन में वीरवार को एक रोमांचक मोटरसाइकिल स्टंट शो का आयोजन किया गया। जिसमें करतब कर रहे जांबांजों ने लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। करीब एक घंटे चले इस रोमांचक स्टंट शो में चार प्रोफेशनल राइडर्स ने केटीएम बाइक्स पर साहासिक करतब पेश किए। यह शो सभी के लिए निःशुल्क था, जिसमें स्थानीय लोगों ने जमकर आनंद लिया। इससे पहले यह स्टंट शो सूरत, अहमदाबाद, कंचीपुरम, मुम्बई, लखनऊ, इंदौर, जम्मू, चंडीगढ़ सहित देश के कोने-कोने में आयोजित किये जा चुके हैं। बजाज केटीएम के प्रोबाइकिंग प्रमुख सुमित नारंग ने बताया कि इन स्टंट शो को आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को कुछ अलग अनुभव करवाना है।

रोपड़ पुलिस ने दिल्ली और यूपी का गैंगस्टर पकड़ा

- माहिर निशानची झुन्ना पंडित कत्ल के 10 मामलों में था वांछित, 1 लाख रुपए का रखा गया था इनाम
- दिल्ली, यूपी और राजस्थान आधारित कई गैर सामाजिक तत्व इस गैंगस्टर के हिमायती हैं

पहला जुर्म 15 साल और पहला कत्ल 16 साल की आयु में किया

ख़तरनाक अपराधी पंडित ने पहला जुर्म 15 साल की आयु में और पहला कत्ल 16 साल की आयु में किया था। उसको दोनों बार 3 साल के लिए जुवेनाइल जेल में रखा गया था। प्राथमिक जांच से पता लगा है कि जेल में होते हुए भी उसने जबरन वसूली, अपहरन की वारदातों समेत 3 कत्ल किये थे। गौरतलब है कि जब भी वह फरार होता था, हवाई यात्रा के जरिए सफर करता था। एसएसपी ने बताया कि हाल ही में की गई जांच से पता लगा है कि ज्यादातर गैंगस्टरों और प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी करने वालों का काम करने का ढंग एक जैसा ही है। वह सफर के लिए स्थानीय रास्तों का प्रयोग करते हैं और आम तौर पर उनके ठिकाने धार्मिक स्थानों के नजदीक होते हैं। पुलिस को इन गैंगस्टरों के काम करने के ढंग का पता लगने के कारण ही पिछले कुछ महीनों में पंजाब-हिमाचल सरहद के नजदीक इन ग़ैर सामाजिक तत्वों की समाज विरोधी गतिविधियों में काफी कमी आई है।

चंडीगढ/लुधियाना। रोपड़ पुलिस ने शुक्रवार को भारी जदो-जहद और दोनों तरफ़ चली गोलीबारी के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अति वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। झुन्ना पंडित पिछले एक वर्ष के दौरान रोपड़ पुलिस की तरफ से पकड़ा गया 11वां गैंगस्टर है।
रोपड़ के एसएसपी स्पन्न शर्मा के अनुसार प्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था और मिर्जापुर, यूपी के तिहरे कत्ल कांड और यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 6 मामलों समेत कत्ल के 10 मामलों में वांछित था। वह दिल्ली और यूपी में कत्ल, जबरन वसूली और अपहरण के 20 से ज्यादा मामलों में शामिल गिरोह को चला रहा है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान आधारित कई गैर सामाजिक तत्व इस गैंगस्टर के हिमायती हैं। रोपड़ पुलिस की सीआईए टीम ने शुक्रवार प्रातः काल उसको पकड़ने के लिए हुई मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर से 32 बोर के 2 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस समेत कई निजी चीजें बरामद की हैं। पंडित और उसके साथी बनारस में दलीप पटेल को सरेआम कत्ल करने के बाद फरार थे। दलीप का भाई राजेश पटेल यूपी के किसान मोर्चा का प्रदेश प्रधान है।
झुन्ना पंडित गिरोह के 8 मेंबर दिल्ली और यूपी की जेलों में बंद हैं और इस गिरोह द्वारा किए गए ज्यादातर जुर्म सुपारी-हत्याओं और अंतर-गिरोह दुश्मनी से संबंधित हैं। एसएसपी के मुताबिक पंडित को एक माहिर निशानची के तौर पर जाना जाता है, जो किसी भी तरह के हथियार को चला सकता है और अपने दोनों हाथों से किसी भी हथियार के साथ गोली चला सकता है। वह यूपी से भागने के बाद दिल्ली, जयपुर और माउंट आबू में गुप्त ठिकानों पर छिपा हुआ था और चिंतपुरनी (हिमाचल प्रदेश) से दिल्ली वापस आ रहा था।

संपादकीय

जन्नत की राह

सर्दियों की दस्तक से पहले ही घाटी में नई बयार की उम्मीद दिखने लगी है। सरकार ने अपनी वह एडवाइजरी वापस ले ली है, जिसमें देश- दुनिया के पर्यटकों को फिलहाल कश्मीर न जाने की सलाह दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के तुरंत बाद ही यह एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। इसके बाद पर्यटक ही नहीं, वहां काम या व्यवसाय कर रहे दूसरे प्रदेशों के लोग, तीर्थयात्री और पढ़ाई करने वाले छात्र भी राज्य से बाहर आ गए थे। वैसे इस तरह की एडवाइजरी का अर्थ किसी तरह की पाबंदी नहीं होता, इसका अभिप्राय सिर्फ इतना होता है कि यह इलाका फिलहाल यात्रा के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। बाद में आई कई खबरों से यह भी पता चला कि इस दौरान भी कुछ विदेशी पर्यटक गए थे और इनमें से कुछ का दावा था कि भीड़भाड़ न होने के कारण वे इस जन्नत के प्राकृतिक नजारों का लुत्फ ज्यादा अच्छी तरह से ले सके। उनकी सकुशल यात्रा यही बताती है कि घाटी में खतरा उतना नहीं था, जितनी आशंका थी। सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी दरअसल एक सावधानी भर थी, जो ऐसे संवदेनशील मौकों पर जरूरी हो जाती है। यह सावधानी पिछले 67 दिनों से जारी थी और अब खुद सरकार की समझ में भी आ गया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस एडवाइजरी को जाना ही था।

मामला सिर्फ पर्यटकों के लिए जारी एडवाइजरी का ही नहीं है, जम्मू- कश्मीर के हालात कई तरह से पटरी पर आते दिख रहे हैं। जनजीवन पर लागू कई तरह की पाबंदियों को हटाया जा चुका है। बुधवार को श्रीनगर की कुछ सड़कों पर हुआ ट्रैफिक जाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, वहां नजरबंद किए गए कई बड़े नेताओं को अब तक रिहा किया जा चुका है। अगले कुछ रोज में मुख्यधारा के ज्यादातर नेताओं के रिहा किए जाने की उम्मीद है। चंद रोज बाद ही कश्मीर में ब्लॉक विकास परिषदों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों की तैयारियां भी जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। इस बीच सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते वहां से आतंकवादी वारदातों की खबरें भी बहुत कम आ रही हैं। पर इन सभी चीजों के बीच पर्यटन एडवाइजरी का वापस लिया जाना महत्वपूर्ण इसलिए है कि कश्मीर में पर्यटन ही सबसे मुख्य व्यवसाय है। यह बहुत से लोगों के रोजगार का जरिया भी है। पर्यटन को फिर से शुरू किए बिना यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि जम्मू-कश्मीर पटरी पर लौट आएगा। अभी जो हालात हैं, उनमें यह उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि एडवाइजरी के हटते ही दुनिया भर के पर्यटन भारी संख्या में कश्मीर पहुंचने लगेंगे। इससे सिर्फ यह पहली बाधा दूर हो गई है, जो कश्मीर जाने के इच्छुक पर्यटकों को अपने फैसले पर फिर से विचार के लिए बाध्य करती थी। लेकिन देशी-विदेशी पर्यटकों का एक बड़ा तबका है, जो जम्मू-कश्मीर का रुख तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाता कि वहां पूरी तरह अमन-चैन है। जाहिर है कि इसमें थोड़ा-सा वक्त लगेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है, उससे यह उम्मीद तो बंधती ही है कि यह वक्त बहुत लंबा नहीं होगा। जम्मू- कश्मीर के हालात सामान्य हों, यह सिर्फ इस प्रदेश के नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए भी बहुत जरूरी है, और सबकी यही प्राथमिकता भी है।

प्रदूषण की चुनौती

प्रदूषण को लेकर एक ही दिन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबर है। अच्छी खबर यह है कि इस बार दशहरा पर रावण दहन पर काफी कम प्रदूषण हुआ वहीं बुरी खबर यह है कि अगले हफ्ते से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता बिगड़ने का अंदेशा है। प्रदूषण बढ़ने के पीछे की दो अहम वजहें हैं। पहला है; पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर पराली का जलाना और दूसरा कारण है मॉनसून की देरी से विदाई। यानी एक वजह मानवीय है तो दूसरा प्राकृतिक। मगर मानवीय कारकों से प्रदूषण का बढ़ना इसलिए चिंता की बात है क्योंकि पिछले कुछ सालों से इस दिशा में काफी चौकसी बरती गई। जनता को जागरूक करने का काम भी व्यापक तौर पर किया गया मगर लगता है, जमीनी स्तर पर यह नहीं पहुंच सका। हाल के दिनों में हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की रौंगटे घटनाएं सामने आई हैं। कई किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं मगर ऐसी कार्रवाइयां ''नक्कारखाने में तूती की आवाज' बनकर रह जाती है। पर्यावरणविदों के साथ-साथ सरकार के लिए अब चुनौती ज्यादा बड़ी है। पिछले ढाई महीने से दिल्ली-एनसीआर के लोग साफ हवा में जी रहे थे। मगर अब हालात बिगड़ने का अंदेशा जोर पकड़ रहा है। लिहाजा प्रदूषण का बारीकी से अध्ययन कर रही एजेंसियों को अब स्थिति को काबू में करने के बारे में कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। फिलहाल पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रणएवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली और आसपास के शहरों में बिजली आपूत्तर्र 24 घंटे सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही पराली जलाने पर रोक के लिए टास्क फोर्स बनाने की महती जरूरत है। बिना इस पर रोक लगाए प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन जगहों को चिह्नित करने की भी जरूरत है, जहां प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा, कूड़ा जलाने वालों पर सख्ती करने की भी जरूरत है। उनपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी हो तो लोगों में डर रहेगा। चूंकि 15 अक्टूबर के बाद ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम (ग्रैप) लागू हो जाएगा तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ज्यादा अहम हो जाएगी। कुल मिलाकर प्रदूषण की समस्या वैसे तो देश भर में पसर रही है, किंतु दिल्ली-एनसीआर इससे कुछ ज्यादा आतंकित रहे हैं। इस बाबत चौकस, सजगता और समझदारी से इसपर नियंत्रणपाया जा सकता है।

परिधि/विशाल तिवारी

अदना सा मुल्क, लंबी छलांग

अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश का जिक्र होते ही यहां से वाली घुसपैठ सबसे पहले जेहन में आती है। भारत में यह एक बेहद गंभीर राजनीतिक-सामाजिक मुद्दा बन चुका है। असम की तर्ज पर एनआरसी को समूचे देश में लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। बीते हफ्ते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे को दौरान लोगों की दिलचस्पी घुसपैठ वाले मामले में ज्यादा थी। अपनी स्थापना के 50 साल पूरे करने जा रहे इस देश ने पिछले दशक में जिस तरह विकास के विभिन्न मानकों पर लंबी और तगड़ी छलांग लगाई है, वह वाकई काबिलेतारीफ है। इसकी चर्चा इसलिए भी जरूरी थी कि अपने जन्म में आया की भूमिका निभाने वाले भारत को भी इसने ''मानव विकास सूचकांक' में पीछे छोड़ दिया। वह शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुछ सामाजिक क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है। खासकर मानव विकास सूचकांक में इस अदने से पड़ोसी की तरक्की भारत के लिए एक नसीहत है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बांग्लादेश 2016 से 7 फीसद की विकास दर बनाए हुए है, जो 8 फीसद के करीब पहुंच सकती है। भारत के साथ-साथ समूचे दक्षिण एशिया के लिए बांग्लादेश में हो रहे बदलाव को अच्छा संकेत कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि यह बदलाव कुछ महीनों में हुए हैं। बदलाव की झलकियों से दुनिया उस समय रूबरू हुई, जब अपने ग्रामीण बैंकिंग प्रयोग के माध्यम से लाखों लोगों को गरीबी से निकालने वाले मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आज बांग्लादेश की तरक्की की कहानी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कपड़ा बाजारों में मिल जाएगी, जहां ''मेड इन बांग्लादेश' छाया हुआ है। 1971 में एक खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के साथ जन्म लेने वाले इस देश की पहचान दुनिया के बेहद गरीब मुल्कों में होती थी, मगर कट्टरपंथ की हवाओं के बीच शेख हसीना के विवेकी नेतृत्व में जिस तरह बांग्लादेश की आज चर्चा हो रही है, वह विशेषकर भारत के लिए भी राहत की खबर है, जिसे जिम्मेदार पड़ोसियों की अदद आवश्यकता है।

क्यों पिछड़ जाते हैं भारत के किसान

चित्रा सुब्रमण्यम

व्यापार समझौते करने वाले वार्ताकार तीन तरह के होते हैं। वार्ताकारों का पहला वर्ग वह होता है, जो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का नुमाइंदा होता है, और जो अपने लोगों के वास्ते सबसे बेहतर समझौता हासिल करने के लिए तमाम साधनों और ताकत का इस्तेमाल करता है। दूसरा वार्ताकार वर्ग वह होता है, जो अपने औपनिवेशिक अतीत, नए व्यापार नियमों और राष्ट्र के समूहों व राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बीच फंसा होता है। ऐसे सभी उसे अलग-अलग दिशा में खींचते रहते हैं। ऐसे वार्ताकार देशों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत भी इन्हीं देशों में एक है।

कपास और वस्त्र जैसे उत्पादों पर, जिनका वैश्विक बाजारों में स्वतंत्र रूप से कारोबार नहीं हो रहा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम उचित रूप से लागू नहीं हैं। फिर भी, इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। एक किलो कपास उगाने में भारत में 0.95 डॉलर (लगभग 67 रुपये) खर्च आता है, जो दुनिया में सबसे सस्ता है। लिहाजा तर्क तो यही कहता है कि दुनिया के कपास बाजार में भारत का बोलबाला होना चाहिए था। मगर इस राह में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों की बेड़ियां हैं। इन्हें तय करने में अब किसी युद्ध की तरह भयंकर जंग लड़ी जाती है।

जब मैं इन पंक्तियों को लिख रही हूं, तब 150 से अधिक देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बैनर तले जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय कपड़ा व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। यहां 7 अक्तूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया था, जो तथाकथित 'कॉटन-4' (बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली का समूह) की एक पहल है और जिसे डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र के कुछ संगठनों का समर्थन हासिल है। ऐसे में, बहुपक्षीय व्यापार के इतिहास की उस असंगत नीति का जिक्र यहां लाजिमी है, जो लंबे समय से कायम है। यह नीति मल्टी फाइबर एग्रीमेंट (एमएफए) है, जो एक ऐसा समझौता है, जिसके तहत अमीर देशों ने अपनी मिलों की रक्षा के लिए छह दशकों से भी अधिक समय से भारत जैसे विकासशील देशों से आयात का कोटा तय कर रखा है। यह समझौता टैरिफ और व्यापार पर आम करार (गैट) के मुक्त-व्यापार नियमों से अलग है। वैश्विक बाजारों में जरूरतों को देखते हुए भारत का यह मानना था कि यदि वह पेटेंट जैसे नए मसलों पर अमेरिका की बात मान लेता है, तो कपड़ा और अन्य निर्यात पर उसे कुछ राहत मिल सकती है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ।

जिनेवा बैठक का जो खाका सामने आया है, उसमें यह साफ नजर आता है कि व्यापार के प्रबंधन में शक्तिशाली देशों को तवज्जो दी गई और उसी छल-बल का इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा विदेशी उत्पादों व सेवाओं पर गरीब देशों की स्थाई निर्भरता सुनिश्चित की जाती है। उपनिवेशीकरण के नियमों पर बेशक अब चर्चा हो रही है, लेकिन लगता यही है कि विकासशील देशों के साथ बस स्वांग रचाया जा रहा है। भारत ने यहां अच्छा भरोसा दिखाया, लेकिन व्यापार वार्ता में शायद ही कभी यह भरोसा कारगर साबित होता है।

कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौता (एओए) बतौर उदाहरण

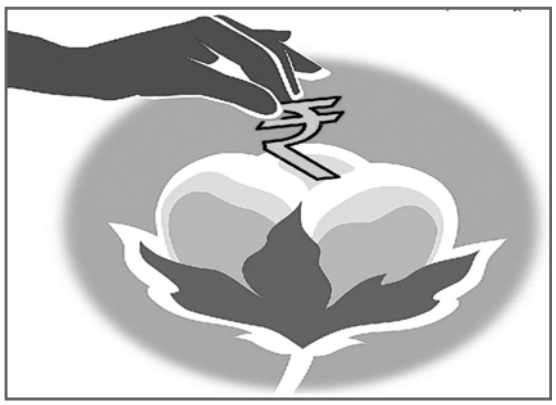

> अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में हमारे देश के किसान किस तरह मात खाते हैं, इसे कपास के उदाहरण से समझा जा सकता है।

सामने है। यह दरअसल सरकारों की तरफ से किसानों को मिलने वाली रियायत और समर्थन बांटने वाला एक सिस्टम है। इस समझौते के तहत, सदस्य राष्ट्र एग्रीमेंट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (एएमएस) के तहत उत्पादों के आधार पर या सामान्य सब्सिडी देकर अपने किसानों की मदद कर सकता है। मगर यह सहायता एक तयशुदा सीमा तक ही की जा सकती है। अमेरिका अपने किसानों को सालाना 19 अरब डॉलर की मदद देता है। इससे वहां भारतीय कपास स्पर्द्धा में पिछड़ जाती है।

एओए नियमों के मुताबिक, विकासशील देशों में कृषि उत्पादन लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत ही मदद हो सकती है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था के लिए यह सीमा पांच फीसदी है। मगर कपास उगाने वाले भारतीय किसानों को पश्चिम (खासतौर से अमेरिका) के किसानों की तरह कोई सब्सिडी नहीं मिलती। इस कारण उनके लिए विदेश के बड़े बाजारों में अपनी पकड़ बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत का इतिहास और अर्थशास्त्र उनकी स्थिति को और बदतर बना देते हैं।

इस प्रसंग की चर्चा यहां इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह पश्चिम की मंशा का भी भंडाफोड़ करता है। दरअसल, एमएफए को दस साल के भीतर हटाने की प्रक्रिया एक जनवरी, 1995 को शुरू हुई। उस वक्त यूरोपीय, अमेरिकी और अन्य अमीर आयातकों ने अपने 16 फीसदी कपड़ा व्यापार को एमएफए के दायरे से बाहर निकालकर उसे डब्ल्यूटीओ द्वारा तय प्रतिबंध या कोटा के सामान्य नियमों में शामिल कर दिया। अगले तीन चरणों में सभी प्रतिबंध या कोटा खत्म होने वाले थे, और 31 दिसंबर, 2004 को घड़ी की सुई के 12 बजाते ही कपड़ा व्यापार मुक्त हो जाता।

मुक्त-व्यापार के दायरे में पैराशूट और सीट बेल्ट से लेकर महिलाओं के पेटीकोट और फर्श कवर बनने वाले उत्पाद रखे गए। गैट के उलट डब्ल्यूटीओ एकमात्र संस्था थी। देश उन उत्पादों को नहीं चुन सकते थे, जिन्हें वे बाहर रखना चाहते थे। नतीजतन, एक-दूसरे देशों से खासा बदला लिया गया। मसलन, यदि आप किसी देश का स्टील नहीं खरीदते, तो वह अपने यहां आपके आम की आवक रोक सकता है। दिल्ली का अपना गणित भी इसी नीति को आगे बढ़ाता है।

भारत सहित गरीब देशों के किसानों में कपास की खेती को लेकर एक नया आकर्षण पश्चिम में आधुनिक खादी पहनने को लेकर होने वाले फैशन शो पैदा कर रहे हैं।

मुक्त व्यापार की जंग में पेटेंट और सूचना प्रौद्योगिकी का जो हश्र है, वही भारत से निर्यात होने वाले कपास और कपड़े का माना जाता है। देश में खादी और कपास को लेकर कई प्रयास तो हुए, पर वे लागत और मूल्य के बीच के अंतर को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानने में विफल रहे हैं। इसलिए अवसर यह सुनने को मिलता है कि 'इसकी लागत सिर्फ पांच डॉलर (करीब साढ़े तीन सौ रुपये)' है, जो यूरोप में या फिर दिल्ली के पॉश इलाकों में दस गुना अधिक कीमतों में बिकता है। आज दुनिया भर के देश अपने राष्ट्रीय उत्पादों को महत्व देते हैं और उन्हें राष्ट्रीय खजाना मानते हैं। खादी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा से जुड़ी रही है। आखिर कब तक हम इसे लेकर मौजूदा वैश्विक कारोबारी नियमों के तहत संघर्ष करते रहेंगे?

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

चर्चित चेहरा

निरंकुश राजशाही तले लोकतंत्र की कछुआ चाल

अरुण नैथानी

पहली नजर में तो लगता है कि सऊदी अरब के ताकतवर युवराज मोहम्मद बिन सलमान रूढ़िवादी सऊदी अरब को आधुनिक बनाने की तरफ बढ़ चले हैं। उन्होंने सऊदी अरब के बंद समाज में सिनेमाहाल खोलने की इजाजत दी, संगीत पर से प्रतिबंध हटाया है, महिलाओं को कार चलाने की अनुमति मिली है, होटलों में विदेशी अविवाहित जोड़े ठहर सकते हैं। वे अपनी कल्पनाओं का एक अद?भुत शहर बसाने जा रहे हैं। अरबों डालर की इस परियोजना को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौर ऊर्जा व इंटरनेट द्वारा संचालित किया जायेगा। लेकिन वहीं बहुचर्चित पत्रकार जमाल खशोगी की रहस्यमय हत्या की सूई उनकी तरफ मुड़ी है। तमाम सुधारवादी, महिला अधिकारों के पक्षधर तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति के पैरोकार जेलों में ठूंसे गये हैं। दूसरी ओर यमन पर सऊदी हमले के जरिये उन्होंने एक मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है।

बावजूद इसके युवराज सलमान मोहम्मद बिन सलमान आज मध्य-पूर्व के सबसे ताकतवर शख्स के रूप में जाने जाते हैं। वे खुद को आधुनिक तथा उदारवादी दिखाने का प्रयास करते हैं। वे सुधार तो चाहते हैं मगर जन आंदोलन के जरिये नहीं। वे चाहते हैं कि सुधार के जो कदम उठाये जायें, वे राजसत्ता के जरिये ही सामने आयें। आंदोलन उन्हें स्वीकार्य नहीं है। सलमान की परवरिश सऊदी शाही परिवार के अन्य हजारों राजकुमारों की तरह ही हुई है। उनका जन्म 31 अगस्त, 1985 को हुआ। उनकी परवरिश समाज से अलग राजमहल में भोग-विलास की तमाम सुविधाओं के मध्य हुई। वे अपने पिता बादशाह सलमान की तेरह संतानों की तरह ही राजमहल में ही पले-बढ़े। जहां उनकी सेवा में जुटे हजारों लोगों की फौज तैनात थी। उनकी बचपन से ही पढ़ने-लिखने में दिलचस्पी थी। अन्य राजकुमारों को जब अमेरिका, ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों में पढ़ने के लिये भेजा गया तो उन्होंने देश में ही पढ़ाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने किंग सऊदी विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री ली। वे राष्ट्रवादी तेवरों वाले देश में यह धारणा बनाने में कामयाब रहे कि वे जमीन से जुड़े राजकुमार हैं। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन विदेश न जाने का एक नुकसान यह रहा कि उनकी अंग्रेजी में पकड़ ढीली रही?और पश्चिमी को समझने में उन्हें काफी वक्त लगा।

इसके साथ ही सलमान देश में रहते हुए अपने पिता के करीब आये और राजकाज की बातों को करीब से समझने लगे। उनके पिता जब रियाद के गवर्नर थे तो हर राजकीय कार्य में वे पिता के साथ साये की तरह रहे। उन्होंने धीरे-धीरे सऊदी शासन के गुर सीखे। फिर धीरे-धीरे उन्हें महत्वपूर्ण पद दिये जाने लगे। महज 27 साल की उम्र में वे पिता के दरबार में वजीर-ए-आला नियुक्त हुए। वर्ष 2015 में कैबिनेट मंत्री बने।

कालांतर वर्ष 2015 में जब सऊदी बादशाह अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो उनके सौतेले भाई सलमान बादशाह बनाये गये। कालांतर मोहम्मद बिन सलमान को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इसी बीच सऊदी अरब की सीमा से लगे यमन में ईरान समर्थित हूती कबीले ने राजधानी सना पर आक्रमण कर निर्वाचित राष्ट्रपति का तख्ता पलट दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने दस देशों का गठबंधन बनाकर यमन पर हवाई हमला बोल दिया। मकसद ईरान को सख्त संदेश देना भी था। लेकिन यह मुहिम कामयाब नहीं हुई और सऊदी अरब के लिये न भरने वाला जख्म साबित हुआ। हाल में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला बोलकर भारी तबाही मचायी। यमन भी बड़ी मानवीय त्रासदी का सामना कर रहा है।

इसी बीच जून, 2017 को एक बड़े ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम में बादशाह सलमान ने युवराज मोहम्मद बिन नफे को अपने से बहुत छोटे युवराज मोहम्मद बिन सलमान के लिये वली अहद का पद छोड़ने के लिये कहा। लंबे अर्से से देश के गृहमंत्री और आतंकविरोधी अभियान के अगु?वा रहे अनुभवी नफे की लंबे अर्से तक सत्ता में भागीदारी रही थी। कायदे से यह एक रक्तहीन तख्तापलट जैसा था। इसके बाद ताकतवर बनते ही प्रिंस सलमान ने सितंबर, 2017 में सभी मुख्य राजकुमारों, कारोबारियों और महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिना आरोप के गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल के बजाय एक आलीशान होटल में रखा गया। उन्हें चेताया गया कि अवैध तरीके से कमाये गए अरबों रियाल की संपत्ति सरकार को सौंप दें। दरअसल, भ्रष्टाचार मुहिम के नाम पर सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। बहरहाल, इसके बावजूद उन्होंने तेल केंद्रित अर्थव्यवस्था में बदलाव लाकर निवेश जुटाकर लाखों बेरोजगार सऊदी युवाओं को रोजगार भी दिलाया। वे एक ऊर्जावान तथा बदलावकारी शासक के रूप में जाने जाते हैं, मगर निरंकुशता उसका आधार है। दामन में कई दाग हैं मगर लाखों युवाओं के हीरो भी हैं। उनके महत्वाकांक्षी विजन 2030 की चर्चा होती है। बादशाह के बाद वे निश्चित रूप से दशकों के लिये मध्य-पूर्व के सबसे ताकतवर शहंशाह होंगे।

कांग्रेस

खुद ही डुबो रही नैया

मुफीज जिलानी

लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह से चरमरा कर रह गई है। कई बड़े नेता, सांसद, विधायक पार्टी को बाय बोलकर या तो भाजपा में शामिल हो गए या किसी अन्य दल का दामन थाम लिया। कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी में तो हैं, लेकिन खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और इंतजार की मुद्रा में हैं। दरअसल, चुनाव में हार के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना और लाख मनाए जाने के बावजूद उनका अपने इस फैसले पर अडिग रहना पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में उदासी और मायूसी पैदा कर गया है। यही नहीं राहुल की इस घोषणा के बाद भी कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेगा, सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने से टीम राहुल में मायूसी और गहरी हो गई, क्योंकि इसके बाद राहुल ने एक तरह से पार्टी में अपनी सक्रियता पर विराम लगा दिया। सोनिया के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही उम्र पार कर चुके जो कांग्रेसी राहुल के अध्यक्ष रहते पार्टी में अपने को भूमिका विहीन और महत्वविहीन समझने लगे थे वह एक बार फिर फूट फूट पर खेलने लगे। वहीं टीम राहुल में शामिल सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, संजय निरूपम, मिलिंद देवड़ा, अशोक तंवर, जितिन प्रसाद जैसे कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके नेता बैकफुट पर चले गए। इस सबके बावजूद राहुल खामोश हैं। उनके ब्लाक के अशोक तंवर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धमकी पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पद से हटा दिया जाता है और राहुल खामोश बने रहते हैं। यहां तक कि तंवर पार्टी छोड़ जाते हैं और अब पार्टी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मिलिंद देवड़ा पार्टी में पूरी तरह महत्वविहीन हो गए पर राहुल खामोश हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने-सामने हैं मगर राहुल चुप हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को हटाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा जोर लगाए हुए हैं। ऐसे और भी तय हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि धीरे-धीरे पुराने और नयों के बीच खुले तौर पर वाकयुद्ध शुरू हो गया है। यह वाकयुद्ध अब तमाम मर्यादाएं भी तोड़ता जा रहा है। जब संजय निरूपम कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता मल्लिकाजरुन खड़गे को नास्तिक कह कर उन पर हमला बोलते हैं। वह कहते हैं, ''मैं जानता हूं कि मल्लिकाजरुन खड़गे जी नास्तिक हैं। वह प्रार्थना, पूजा में विास नहीं करते। लेकिन उनकी तरह कांग्रेस में सभी लोग नास्तिक नहीं हैं।' शस्त्र पूजा भारत की परंपरा है तमाशा नहीं। यह बात निरूपम ने राजनाथ द्वारा फ्रांस में राफेल की पूजा किए जाने पर की गई खड़गे की टिप्पणी पर कही थी। सलमान खुर्शीद राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने पर जब बोलते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि सब कांग्रेसी उनसे पद पर बने रहने का आग्रह और विनती कर रहे थे, तो राशिद अल्वी उन पर टूट पड़ते हैं। यहां तक कह देते हैं कि कांग्रेस को बाहर के दुश्मनों से नहीं अंदर से खतरा है, बल्कि यों कहो ''घर को आग लग गई घर के चिराग से'। ज्योतिरादित्य का दर्द भी बाहर आ जाता है वह भी लगे हाथ नेतृत्व को नसीहत दे बैठते हैं।

सिंधिया कहते हैं, ''मैं किसी के कमेंट पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा। लेकिन हां, इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस को आत्मावलोकन की जरूरत है। यह सही भी है होना भी चाहिए, लेकिन क्या ज्योतिरादित्य खुद इस नसीहत के दायरे में नहीं आते। यह सब देख-सुनकर साफ है कि फिलहाल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में समर्पण की कमी साफ नजर आ रही है। ऐसा लगता है अपने को कांग्रेसी कहने वाले ज्यादातर लोग मौके की तलाश में हैं। मौजूदा हालात में ऐसा कोई नेता या कार्यकर्ता नजर नहीं आता जो पार्टी को फिर से खड़ा करने का जतन कर रहा हो। अब तो एक और बात लगातार सामने आ रही है कि साधारण दल के चक्रव्यूह में कुछ नेता ऐसे फंस गए हैं कि वे पार्टी लाइन से हटकर जनभावनाओं की आड़ लेकर सत्ताधारी दल की कतार में खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस आज जिस दौर से गुजर रही है ऐसी हालत 1977 में भी नहीं रही, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा और गिने-चुने नेताओं के अलावा पार्टी का कोई नेता पार्टी के प्रति संजीदा नजर नहीं आता। देश की जनता भी सत्ता के खिलाफ किसी सशक्त विपक्ष के अभाव में अपने को एकदम असहाय महसूस कर रही है। यही हालत रही तो वह दिन दूर नहीं जब आरएसएस और आरएसएस नवाजों का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो जाएगा। सब ''ईसा अपनी राह मूसा अपनी राह' की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

पेटीएम ने दिया ग्राहकों को झटका, बचत खाते पर चलाई कैंची

बिजनेस डेस्क(एजेंसी)।

अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पेटीएम ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज को कम किया है। पेटीएम भुगतान बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में आधा फीसदी की कटौती कर 3.5 फीसदी कर दिया है। पेटीएम बैंक की ओर से जारी बयान में बताया गया कि यह कटौती 1 नवंबर से प्रभावी होगी। इसके साथ ही पेटीएम भुगतान बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सावधि जमा योजना (एफडी) की भी घोषणा की है। हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सेविंग अकाउंट की जमा राशि पर कैंची चलाई है। एसबीआई सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा रखने वालों को 3.25 फीसदी के हिसाब से ब्याज देगा। अब पेटीएम भुगतान बैंक (पीपीबी) ने भी अपने ग्राह को को झटका दिया है। इसका असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिनका पेटीएम भुगतान बैंक में सेविंग अकाउंट है। बैंक के एमडी सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि रिजर्व बैंक ने हाल में रेपो रेट को चौथाई फीसदी घटाकर 5.15 प्रतिशत कर दिया है। पिछले 12 माह में केंद्रीय बैंक रेपो दर में 1.35 फीसदी की कटौती कर चुका है। इस वजह से यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा पेटीएम ने दिया ग्राहकों को झटका, बचत खाते पर चलाई कैंची ग्राहकों को एक रुपए में भी एफडी खाता खोलने का मौका देता है। पेटीएम एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज देता है।

दिल्ली: मदर डेयरी की सभी दुकानों पर 40 रुपये किलो मिलेगा टमाटर, केंद्र सरकार ने किया फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)।

उपभोक्ताओं को टमाटर की ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की मदर डेयरी को शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सफल ब्रांड 400 दुकानों के जरिये टमाटर की प्यूरी बेचने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में यह फै सला किया गया। बैठक में टमाटर की कीमतों और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। टमाटर जल्दी खराब होने वाली सब्जी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के खुदरा बाजारों में टमाटर 80 रुपये किलो की ऊंचाई पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे उत्पादक राज्यों में भारी बारिश की वजह से टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली में टमाटर की कमी को दूर करने के लिए सफल ने अपनी सभी दुकानों

के जरिये टमाटर की प्यूरी बेचने की सहमति दी है। टोमैटो प्यूरी के 200 ग्राम का पैक (800 ग्राम ताजा टमाटर के बराबर) 25 रुपये के स्टॉक को सभी दुकानों में और 825 ग्राम का पैक (ढाई किलो टमाटर के बराबर) बेचा जाएगा।

बयान में कहा गया है कि प्यूरी पहुंचा दिया गया।

इफको ने यूरिया को छोड़ अन्य उर्वरकों का खुदरा मूल्य 50 रुपए प्रति पैकेट कम किया

नई दिल्ली(एजेंसी)।

इफको ने वैश्विक स्तर पर कच्ची सामग्रियों तथा तैयार उर्वरकों के दाम में आ रही कमी के मद्देनजर डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) समेत जटल उर्वरकों का खुदरा मूल्य शुक्रवार को प्रति पैकेट 50 रुपए तक कम कर दिया। इफको के प्रबंध निदेशक यू.एस.अवस्थी ने कहा, ''कच्ची सामग्रियों तथा तैयार उर्वरकों के दाम में वैश्विक स्तर पर आ रही कमी को देखते हुए हमने डीएपी तथा सभी जटिल उर्वरकों का खुदरा मूल्य कम किया है। उन्होंने कहा कि इफको ने डीएपी के 50 किलोग्राम के पैकेट का अधिकतम खुदरा मूल्य 50 रुपए घटाकर 1,250 रुपए कर दिया है। इसी तरह एनपीके-1 और एपनीके-2 के पैकेट का दाम 50-50 रुपए घटाकर क्रमशः 1,200 रुपए और 1,210 रुपए कर दिया गया है। एनपी कॉम्पलैक्स का दाम भी 50 रुपए घटाकर 950 रुपए किया गया है। अवस्थी ने कहा कि संशोधित कीमतों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल है। नयी कीमतें 11 अक्टूबर से प्रभावी होंगी।

नीम कोटेड यूरिया के 45 किलोग्राम के पैकेट की कीमत 266.50 रुपए ही रहेगी। इफको ने इससे पहले डीएपी और जटिल उर्वरकों का भाव इस साल जुलाई में कम किया था।

इन्फोसिस का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 2.2प्रतिशत घटकर 4,019 करोड़ रुपए पर

नई दिल्ली(एजेंसी)।

देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी इन्फोसिस का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 2.2 प्रतिशत घटकर 4,019 करोड़ रुपए रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 4,110 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बेंगलुरु की कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी आय 9.8 प्रतिशत बढ़कर 22,629 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 20,609 करोड़ रुपए थी। इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष के अपनी आमदनी के नीचे के अनुमान को संशोधित किया है। इन्फोसिस का अनुमान है कि स्थिर मुद्रा में उसकी आमदनी में 9-10 प्रतिशत का इजाफा होगा। पहले कंपनी ने इसमें 8.5 से 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सलिल पारेख ने कहा कि कई मोर्चों राजस्व वृद्धि, डिजिटल वृद्धि, परिचालन मार्जिन, परिचालन दक्षता, बड़े करार पर दस्तखत तथा कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर पर हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

सोना 50 रुपए चमका, चांदी स्थिर

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 50 रुपए चढ़कर 5 सप्ताह के उच्चतम स्तर 39,570 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया जबकि चांदी 47,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। लंदन तथा न्यूयॉर्क से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोना हाजिर 5.50 डॉलर चमककर 1,498.45 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। व्यापार युद्ध और ब्रेग्जिट पर बनी अनिश्चितता के बीच निवेशकों की सतक र्लिवाली से पीली धातु को समर्थन मिल रहा है। दिसंबर का अमेरिकी सोना वायदा भी तीन डॉलर की बढ़त में 1,503.90 डॉलर प्रति औंस बोला गया। चांदी हाजिर 0.17 डॉलर की उछाल के साथ 17.64 डॉलर प्रति औंस के भाव बिकी।

इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 500 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदेगी

नई दिल्ली। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ने 100 रुपए मूल्य के पांच करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की है। इस पर कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। शेयरों की वापस खरीद कंपनी के शेयर के मौजूदा मूल्य से दोगुने से अधिक पर की जाएगी। बंबई शेयर बाजार में अभी कंपनी का शेयर 43.40 रुपए पर चल रहा है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने शुक्रवार को पांच करोड़ पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 100 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर कुल चुकता इक्विटी पूंजी का करीब 11 प्रतिशत है। यह पुनर्खरीद निविदा पेशकश के जरिए की जाएगी। कंपनी के निदेशक मंडल ने एक पुनर्खरीद समिति का गठन किया है जिसके पास इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन का अधिकार होगा।

कारों की बिक्री में गिरावट जारी

नई दिल्ली। देश में वाहनों की बिक्री में गिरावट का रुख इस वर्ष सितंबर में भी बना रहा। इस महीने में कारों की बिक्री में 33.40 प्रतिशत की गिरावट रही। ऑटो मोबाइल कम्पनियों का संगठन सियाम के शुक्रवार को यहां जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में देश में 134281 कारों की बिक्री हुई जो पिछले वर्ष सितंबर में बेची गई 197129 कारों की तुलना में 33.40 प्रतिशत कम है। इस दौरान उपयोगी वाहनों की बिक्री में 5.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर में 81625 उपयोगी वाहनों की बिक्री हुई जबकि पिछले वर्ष सितंबर में यह संख्या 77380 रही थी।

पुनरुद्धार की योजना पर सरकार कर रही विचार : बीएसएनएल

नई दिल्ली। सरकारी दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को बंद किये जाने को लेकर आ रही खबरों के बीच बीएसएनएल ने गुरुवार को कहा कि उसके पुनरुद्धार की योजना पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। बीएसएनएल ने यहां जारी स्पष्टीकरण में कहा कि कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस)/4जी स्पेक्ट्रम और उसके संपदा के मौद्रिकरण की अनुमति के माध्यम से पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त पैकेज देने की योजना पर सक्रियता से विचार कर रही है। उसने कहा कि बीएसएनएल राष्ट्रीय आपदा जैसे कठिन समय में और दूरस्थ क्षेत्रों में किफायती दरों पर सेवायें दे रही है और भविष्य में भी ये सेवायें जारी रहेंगी। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने के लिए कहा है। मंत्रालय के पास नीति आयोग ने इसमें विनिवेश से जुड़ा प्रस्ताव भेजा था लेकिन उसने विनिवेश के स्थान पर इसको बंद करने की सलाह दी है।

स्मार्टफोन में कुछ नया और खास फीचर्स देने का दौर खत्म!

नई दिल्ली। पिछले 10 साल में मोबाइल फोन की दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीकी बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन, अब इस क्षेत्र में भी ठहराव आ गया है। मोबाइल कंपनियों द्वारा स्मार्टफोन में कुछ नया और खास फीचर्स देने का दौर खत्म हो गया है। मौजूदा समय में बाजार में लॉन्च होने वाले अधिकांश फोन में एक समान फीचर्स ही मिल रहे हैं। वर्तमान में लॉन्च होने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन के डिजाइन एक समान मिल रहे हैं। सभी कंपनियों के फोन में एक या उससे ज्यादा कैमरे मिल रहे हैं। वहीं बैटरी की बात कि जाए तो 3000 एमएएच से लेकर 6000 एमएएच की बैटरी उपलब्ध है। चार्जिंग में भी कुछ खास बदलाव नहीं है। प्रीमियम स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग तकनीक मिल रही है तो सामान्य फोन में डीसी चार्जिंग उपलब्ध कराई जा रही है। सवाल उठता है कि स्मार्टफोन में नए फीचर्स का दौर खत्म हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के दिनों में बैटरी, कैमरा, सुरक्षा को लेकर कई काम हुए हैं। ऐसे में बड़े बदलाव की उम्मीद अभी नहीं है।

लगातार दूसरे दिन घटे पेट्रोल, डीजल के दाम

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल शुक्रवार को दिल्ली और मुंबई में 12 पैसे, कोलकाता में 11 पैसे और चेन्नई में 13 पैसे लीटर सस्ता हुआ। डीजल का दाम भी दिल्ली और कोलकाता में 15 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 16 पैसे प्रति लीटर कम हो गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमशः 73.42 रुपये, 76.07 रुपये, 79.03 रुपये और 76.25 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी घटकर क्रमशः 66.60 रुपये, 68.96 रुपये, 69.81 रुपये और 70.35 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बीते दिनों नरमी रहने से भारत में पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे त्योहारी सीजन में देश के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। बाजार के जानकार बताते हैं कि तेल का दाम बढ़ने से माल-भाड़ा में वृद्धि होती है जिससे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में इजाफा होता है।

जीएसटी संग्रह बढ़ाने को सरकार ने बनाई समिति, 15 दिन के अंदर देनी होगी रिपोर्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)।

सरकार ने जीएसटी वसूली में लगातार गिरावट को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। जीएसटी संग्रह बढ़ाने और इसमें सुधार के लिए अधिकारियों की एक समिति बनाई। यह समिति 15 दिनों के भीतर जीएसटी परिषद को अपनी पहली रिपोर्ट सौंप देगी। सरकार की ओर से गठित समिति यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि जीएसटी संग्रह तय लक्ष्य से पीछे क्यों चल रहा है। साथ ही कारोबारियों द्वारा नियमों का दुरुपयोग रोकने, नियमों का सही से अनुपालन बढ़ाने, कर का आधार बढ़ाने और बेहतर प्रशासनिक तालमेल बनाने के उपायों पर विचार कर सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार साल 2017 में लाए गए अप्रत्यक्ष कर कानून को ठीक करने के बारे में विचार कर रही है। इसलिए समिति को विस्तार से सुझाव देने का निर्देश दिया गया है। आर्थिक सुस्ती के चलते जीएसटी संग्रह सितंबर में 19 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में कुल 91,916 करोड़ रुपये था। वहीं, सरकार का लक्ष्य हर महीने एक लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह करने का है लेकिन इस वित्त वर्ष में ये तीसरा महीना है जब सरकार अपने लक्ष्य से चूकी। जीएसटी घटने से सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ने की आशंका है। सरकार की ओर समिति में 12 सदस्यों की शामिल किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी से जुड़े अधिकारियों के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के जीएसटी अधिकारी भी शामिल रहेंगे। अन्य राज्यों को भी कमेटी में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। लगातार कर संग्रह लक्ष्य से कम रहने की वजह से वित्त वर्ष 2019-20 में जीएसटी संग्रह उम्मीद से 40 हजार करोड़ रुपये कम होने की आशंका है।

बोइंग के 38 विमानों में मिली दरारें, उड़ानें रोकी गईं

न्यूयॉर्क(एजेंसी)।

बोइंग की सुरक्षा संबंधी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दुनियाभर की एयरलाइन कंपनियों ने बोइंग के 737 एनजी विमानों की जांच-पड़ताल की। इसमें तीन दर्जन से अधिक विमानों की बुनियाद में दरारें मिली हैं, जिनकी मरम्मत किए जाने की जरूरत है। बोइंग ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिकी सुरक्षा नियामक के आदेश के बाद दुनियाभर की एयरलाइनों ने 810 विमानों का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि इनमें से 38 या पांच प्रतिशत विमानों की मरम्मत की जरूरत है। एयरलाइन कंपनियों को कुछ बोइंग 737 एनजी विमानों की जांच के लिए कहा गया था। जांच में विमान के फ्यूसलेज को पंखों से जोड़ने वाले हिस्से में दरार मिली हैं। बोइंग ने उन एयरलाइनों का नाम बताने से इनकार किया, जिनकी सुरक्षा में खामियां पाई गईं। बोइंग और एयरलाइन के अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विमानों की मरम्मत होने तक उन्हें जमीन पर खड़ा रखा जाएगा। बुधवार को साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी और ब्राजील के गोल लिन्हास एरेस ने यूएस रेगुलेटर के आदेश के बाद तत्काल जरूरी निरीक्षण के लिए 737 एनजी एअरप्लेन को उतार कर कम से कम 13 विमानों की जांच की। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने पिछले सप्ताह अमेरिकी विमान ऑपरेटरों को 165 पुराने 737 एनजी विमानों में संरचनात्मक दरारों की जांच करने के लिए कहा था। मगर, अब ऐसा लगता है कि जांच किए गए विमानों की वास्तविक संख्या 200 से अधिक है। एफएए ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राज्य में विमान की एक छोटी संख्या को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि बोइंग विमानों के प्रभावित भागों की मरम्मत या बदल रहा है। एजेंसी ने कहा कि वह निर्माता और अन्य अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा नियामकों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि उन कारकों को बेहतर ढंग से समझा जा सके, जिनकी वजह से विमानों में दरारें पैदा हो रही थीं। साउथवेस्ट की प्रवक्ता ब्रांडी किंग ने कहा कि 200 से अधिक ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले हवाई जहाजों में से दो विमानों में दरारें पाई गई हैं और उन्हें जमीन पर खड़ा कर दिया गाय है। हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या अन्य विमानों में भी दरारें मिली हैं। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं बता सकते हैं कि ये विमान कब से सेवा में आएंगे और आगामी मरम्मत के लिए समय तय करने के लिए बोइंग के साथ काम कर रहे हैं।

यूपी-रेरा ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया, 22 परियोजनाओं के प्रवर्तकों को नोटिस जारी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट नियामक (यूपी-रेरा) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 22 रियल्टी परियोजनाओं के प्रवर्तकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये प्रवर्तक कब्जे से संबंधित अदालती आदेश का अनुपालन करने में विफल रहे हैं। उनके नोटिस का जवाब 23 अक्टूबर तक देने को कहा गया है। इन परियोजनाओं के प्रवर्तकों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अजनारा रियलटेक, न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, एसोटेक, सॉलिटेयर इन्फ्राहोम, न्यूटेक ला पैलेसिया, बुलंद बिल्डटेक, हिमालय रियल एस्टेट, आप्लुलेंट इन्फ्रा डेवलपर्स, अर्थकॉन यूनिवर्सल इन्फ्राटेक, पटेल एडवांस जेवी, उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स, एआईएमएस प्रमोटर्स, जीएस प्रमोटर्स और हर्ष एसोसिएट्स। नियामक ने बयान में कहा, ''यूपी रेरा ने कई प्रवर्तकों की 397 ऐसी परियोजनाओं की पहचान की है जिनमें अदालत के कब्जे से संबंधित आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। ये प्रवर्तक शिकायतकर्ताओं को कब्जा देने की अपनी समयसीमा से चूक गए। पहले चरण में 22 परियोजनाओं की पहचान की गई है। यूपी रेरा के सचिव के साथ 23 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक बुलाई गई है।

ऑटो इंडस्ट्री की मंदी बरकरार! सितंबर में यात्री वाहनों की बिक्री 23.7 फीसदी घटी

नई दिल्ली(एजेंसी)।

बीते दो महीनों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं लेकिन सरकार की इन कोशिशों के बावजूद ऑटो इंडस्ट्री की मंदी बरकरार है। दरअसल, वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम ने बताया है कि सितंबर में कारों की बिक्री एक बार फिर लुढ़की है। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक पैसेंजर ० हीकल स की बिक्री 23.69 फीसदी गिर गई है तो वहीं कॉमर्शियल ० हीकल स की बिक्री में 62.11 फीसदी की गिरावट आई है। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में पैसेंजर्स व्हीकल्स के प्रोडक्शन में करीब 19 फीसदी की गिरावट आई है जबकि डोमेस्टिक सेल्स 23.69 फीसदी लुढ़क गया है। सितंबर के महीने में कुल 2,23,317 पैसेंजर ० हीकल स की बिक्री हुई है जबकि 2,79,644 पैसेंजर्स ० हीकल स का प्रोडक्शन हुआ है। सितंबर में पैसेंजर्स कार का प्रोडक्शन 1,80,779 यूनिट रहा जबकि इसी अवधि में बीते साल इस सेगमेंट की 2,33,351 कारों का प्रोडक्शन हुआ था। इस लिहाज से 22.53 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं पैसेंजर्स कार की डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो सितंबर 2019 में 1,31,281 कारों की बिक्री हुई है जबकि इसी अवधि में पिछले साल 1,97,124 कार बिके थे यानी पैसेंजर्स कार की डोमेस्टिक सेल्स में 33 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। अगर यूटिलिटी ० हीकल स के सितंबर में प्रोडक्शन की बात करें तो 2.45 फीसदी गिरावट के साथ 87 हजार 127 रही है जबकि इसी अवधि में बीते साल 89 हजार 319 कारों का प्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा वैन्स की सितंबर के प्रोडक शन में करीब 38 फीसदी की गिरावट आई है और यह 11 हजार 738 पर आ गया है। वैन्स के डोमेस्टिक सेल स की बात करें तो सितंबर में 43 फीसदी की गिरावट आई है। अगर थ्री व्हीलर के प्रोडक शन और डोमेस्टिक सेल स की बात करें तो क्रमशः 1.15 फीसदी और 3.92 फीसदी की गिरावट आई है।

शराब की हेराफेरी में महिलाए सक्रिय

भेस्तान रेलवे स्टेशन के पास शराब के साथ ५ महिला गिरफ्तार

सूरत.

शहर में भले ही पुलिस शराब बंदी होने का दावा करती हो लेकिन आये दिन सामने आनेवाली घटनाओ से पुलिस के दावों की पोल खुल जाती है. इतना ही नहीं चौकादेनेवाली बात तो यह है कि महिलाए भी इन अवैध और गैरकानूनी धंधे में सक्रीय हो गई है.भेस्तान रेलवे स्टेशन के पास पुलिस में शराब के साथ ५ महिलाओ को गिरफ्तार किया.

मिली जानकारी अनुसार पुलिस ने सुचना के आधार पर गत रोज भेस्तान रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज के निचे निगरानी करके शामा संगाडा,गीता डामोर,रेणुका भूरिया,सीता देहदानी और नशीला भूरिया नामक महिलाओ को गिरफ्तार किया था.पुलिस ने इनके पास से अंग्रेजी शराब का ४० हजार से अधिक की कीमत का जत्था बरामद किया था. पांडेसरा पुलिस ने पांचो महिलाओ के खिलाफ मामला दर्ज किया और वे लोग कितने समय से इस धंधे में सक्रीय है और किन के लिए काम करती है इत्यादि जानकारी जुटाने के लिए अग्रिम कार्यवाही शुरू की है.

शहर में स्नेचरों का आतंक जारी

सलाबतपुरा में एक महिला की चेन तो वराछा मोबाइल छीना

सूरत.

शहर में स्नेचर बेखौफ होकर एक के बाद एक घटनाओ को अंजाम देते जा रहे है वही पुलिस उनपर लगाम कसने ने नाकाम साबति हो रही है. अलग अलग घटनाओ में सलाबतपुरा क्षेत्र में स्नेचरों ने एक महिला के गले में से चेन छीनकर तो वराछा में मोबाईल छीनकर भाग गये थे.

मिली जानकारी के मुताबिक्र डिंडोली के महाप्रभु नगर निवासी नयना बेन रणा बुधवार की रात को भाठेना में ओवर ब्रिज के पास से जा रही थी तभी बाइक पर आये दो अज्ञात बदमाश उनके गले में झपट्टा मारकर ३० हजार की कीमत की चेन छीनकर भाग गए थे.घटना से नयना बेन काफी घबरा गई थी. इसी तरह दूसरी घटना में वराछा निवासी ईला बेन खिचडिया गुरुवार शाम को कमलबाग सोसाइटी के पास से जा रही थी उस दौरान बाइक पर आये दो अज्ञात बदमाश मोबाइल और पर्स छीनकर भाग गये थे. इन दोनों घटनाओ में सलाबतपुरा और वराछा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है.

तीन अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत, 3 जिंदा जले

अहमदाबाद। राज्य में तीन अलग अलग जगहों पर हुई दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा घायल हो गए। जिसमें दो बाइक सवार समेत ट्रक ड्राइवरों की जिंदा जलकर मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी गुजरात के पाटन जिले में आज सुबह हारिज-राधनपुर रोड पर लकड़ी से लदे आइशर ट्रक के पीछे मिनी आइशर ट्रक घुस गया। इस हादसे में मिनी आइशर ट्रक के ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दो ट्रकों के बीच फंसे ड्राइवर के शव को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया।

2020 तक राज्य में 1000 सीएनजी स्टेशन शुरू करने की मंशा: मुख्यमंत्री

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात को पर्यावरण प्रिय और प्रदूषण रहित परिवहन सेवा में अग्रणी बनाने के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) का व्यापक उपयोग करने के संकल्प के साथ वर्ष 2020 तक राज्य में 1000 सीएनजी फिलिंग स्टेशन शुरू करने की मंशा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गांधीनगर में सीएनजी सहभागी योजना के अंतर्गत राज्य में गुजरात गैस लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड के परिचालन क्षेत्रों में 214 और सीएनजी स्टेशन शुरू करने के आबंटन पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएनजी के उपयोग से पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन से फैलने वाले धुएं के प्रदूषण से मुक्ति मिलने के साथ ही नए सीएनजी स्टेशन शुरू होने से वाहनचालकों को लंबी कतार में खड़े रहने से भी निजात मिलेगी। विजय रूपाणी ने कहा कि गुजरात ने सीएनजी के उपयोग में भी देश का नेतृत्व किया है। पूरे देश में कार्यरत करीब 1800 सीएनजी स्टेशनों में से 31 फीसदी यानी कि 558 स्टेशन अकेले गुजरात में हैं।

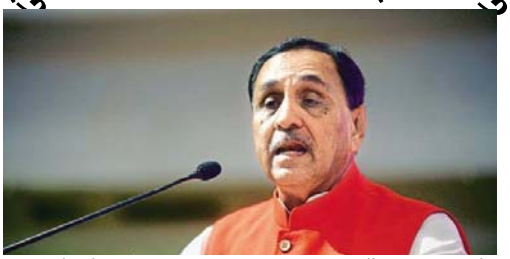

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नए सीएनजी स्टेशन शुरू होने से सीएनजी उपभोक्ता, गुजरात गैस लिमिटेड और पंप संचालकों तीनों के लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण होगा। इन स्टेशनों के कार्यरत होने से स्थानीय स्तर पर लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में 'स्वच्छ और हरित गुजरात' की संकल्पना के साथ जून-2019 में सीएनजी सहभागी योजना शुरू कर करीब 300 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सिर्फ तीन महीनों में ही समूची प्रक्रिया पूरी कर आज 214 स्टेशन शुरू करने के आबंटन पत्रों का वितरण पारदर्शिता, निर्णायकता के साथ त्वरित प्रशासन की प्रतीति कराने वाली घटना है। विजय रूपाणी ने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को गति देने घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर रूफटॉप योजना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देने जैसे अभिनव आयामों के जरिए ग्लोबल वॉर्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की गुजरात की तैयारियों पर रोशनी डाली। उन्होंने नए पंप संचालकों से सीएनजी पंप जल्द से जल्द कार्यरत कर गुजरात के सीएनजी वाहनचालकों को सरलता एवं शीघ्रता से सीएनजी ईंधन मुहैया कराने का दायित्व निभाने का आह्वान किया। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी) के चेयरमैन और राज्य के मुख्य सचिव डॉ. जेएन सिंह ने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में गुजरात देश में शीर्ष स्थान पर है। राज्य में सर्वाधिक गैस कनेक्शन और गैस वितरण व्यवस्था स्थापित की गई है। अब तक प्रतिवर्ष करीब 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित होते थे लेकिन मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिभाषा को मूर्तिमंत करने के लिए उन्होंने 300 से अधिक सीएनजी पंप शुरू करने की चुनौती दी थी। गुजरात गैस और साबरमती गैस कंपनी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आज 200 से अधिक सीएनजी पंपों के आबंटन पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पंपों के निर्माण से पर्यावरण के जतन के साथ-साथ नागरिकों को सस्ती और त्वरित गैस आपूर्ति वाहनों के लिए मिलेगी और वर्चुअल साइकिल बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया होगा तथा गैस डीलरों, गैस कंपनी तथा ग्राहकों को फायदा होगा। जीएसपीसी के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार ने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने मजबूत संकल्प कर जो योजना बनाई है उसके चलते आज राज्य में गैस वितरण व्यवस्था सुदृढ़ बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य के 33 में से 25 जिलों में गुजरात गैस और साबरमती गैस कंपनी द्वारा सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएनजी पंप के नए डीलरों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एम.के. दास, ऊर्जा-पेट्रो विभाग की प्रधान सचिव सुनयना तोमर सहित कई उच्च अधिकारी, पेट्रोलियम एसोसिएशन के पदाधिकारी, गैस वितरण संस्था के चेयरमैन सहित वितरक एवं डीलर बंधु उपस्थित थे।

चंदनीपड़वा के पहले फ़ूड विभाग की जाँच

अलग अलग विस्तारो में मिठाई दुकान में से घारी के नमूने लिए

सूरत.

चन्द्रीपड़वा पर्व पर घारी की भारी मांग होती है. इसलिए कई मिठाई विक्रेता अखाद्य वस्तु बेचकर ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते है.इसलिए चन्द्रीपड़वा से पहले ही मनपा के फ़ूड विभाग द्वारा मिठाई की अलग अलग दुकानों में जाकर घारी के नमूने लिए गए.जानकारी के मुताबिक्र मनपा के फ़ूड विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार को शहर के अलग अलग विस्तारो में स्थित ५ से ६ मिठाइयों की दुकान में जाकर खास तौर से घारी के नमूने लेकर वह खाने लायक है या नहीं, खाद्य या अखाद्य है इत्यादि के परीक्षण के लिए मनपा की लेबोरेट्री में भेजे गए थे. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएंगी.फ़ूड विभाग के अधिकारियो ने बताया कि चाँदनीपड़वा के पर्व के चलते खास तौर से घारी की गुणवत्ता की जाँच के लिए नमूने लिए गए और आगामी दिनों में भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेंगी.

राहुल गांधी ने अहमदाबाद की हेरिटेज होटल अगाशी में किया गुजराती भोजन

अहमदाबाद। मानहानि के दो अलग अलग मामलों में अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होने से पहले वायनाड से सांसद और कांगर्स के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहर की हेरिटेज होटल अगाशी में गुजराती भोजन किया। इससे पहले अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे राहुल गांधी का कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। एयरपोर्ट से कोर्ट तक रास्ते पर राहुल गांधी के पोस्टरों के साथ कांग्रेस बैनर और झंडे लगाए गए। सत्यमेव जयते, लेट्स ट्रूथ प्रीविल, तिरंगा ही मेरा धर्म इत्यादि के बैनर लगाए गए।

ट्राफिक पुलिस ने मास्क वितरण किया

बरसात के बाद फैलने वाले रोगो से बचने का उपाय

सूरत.

ट्राफिक पुलिस और टीआरबी द्वारा मास्क वितरण किया गया. बरसात के बाद विभिन्न रोग फैलते है इसलिए मास्क का उपयोग करने से हवा में पावडर के रूप में फैलनेवाली गंदगी और रोगो से बचा जा सकता है,ऐसा संदेशा दिया गया था.

ट्रैफिक शाखा के एसीपी चौहान ने बताया कि बरसात के बाद कीचड़ सूखा हो जाता है जो सूखा होकर पावडर के रूप में गंदगी फैलाता है .यह गंदगी पावडर के रूप में हवा में फैलती और हवा के जरिये मानवो के शरीर में पहुचतो है जिस वजह से लोग गले,फेफड़े,साइनस जैसे रोगो के शिकार होते है. इसलिए ऐसे रोगो से बचने के लिए सस्ते और सरल उपाय मास्क है. इस प्रकार का संदेश देने के साथ ट्रैफिक पुलिस द्वार मास्क का वितरण किया गया और पुलिस द्वारा अपील की गई कि इस प्रकार के रोगो से बचने के लिये मास्क का उपयोग करे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों गुजरात में हैं

ढाबे पर चाय पीते दिखे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी

अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने एक साधारण से ढाबे पर चाय पी : पार्टी के कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे

अहमदाबाद । कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों गुजरात में हैं। वह यहां किसी रैली या चुनाव प्रचार के लिए नहीं बल्कि कुछ मुकदमों की सुनवाई के लिए पहुंचे हैं। सूरत के बाद शुक्रवार को एक केस की सुनवाई के सिलसिले में अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने एक साधारण से ढाबे पर चाय पी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। खुद राहुल गांधी ने इसका विडियो भी ट्वीट किया। राहुल गांधी को मानहानि के इस केस में जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी ने विडियो के साथ अपने ट्वीट में लिखा, कल सूरत, आज अहमदाबाद । मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर दायर किए गए एक और केस की सुनवाई के लिए पहुंचा हूं। इस शहर में मेरे कांग्रेस परिवार के लोगों से मिलकर और उनके साथ एक स्थानीय रेस्तरां में खाना खाकर अच्छा लगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं । बता दें कि राहुल गांधी मानहानि के कुछ मुकदमों की सुनवाई के लिए पेश होने गुजरात पहुंचे हैं।

शुक्रवार कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया। यह मामला गृह मंत्री अमित शाह को 'हत्या का आरोपी' बताने से जुड़ा है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आरबी इतालिया की अदालत ने १०,००० रुपये के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दे दी। अदालत में राहुल गांधी की खुद को निर्दोष बताने की दलील दर्ज होने के बाद उनके वकीलों ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया। अदालत ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख ७ दिसंबर तय की है।

आत्महत्या के बढ़ते मामले

एक ही दिन में तीन व्यक्तियों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

सूरत.

शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओ से समाज में चिंता का विषय बनता जा रहा है. किसी न किसी कारण को लेकर लगभग शहर में रोज एक व्यक्ति आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है.इसी तरह अलग अलग तीन मामलो में तीन व्यक्तियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

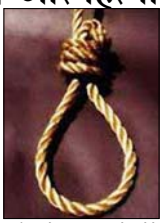

मिली जानकारी के मुताबिक कतारगाम स्थित अंजनी पैलेस एपार्टमेंट निवासी नविन रणछोड़ पटेल (५५ वर्ष) ने गुरुवार दोपहर को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दूसरी घटना में पंडोल निवासी सहदेव भीखा गोहिल (२६ वर्ष) ने कारखाना में लोहे के एंगल से चादर बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसी तरह तीसरी घटना में भटार के गोकुल नगर निवासी आकाश कांति कहार (२० वर्ष) ने गत रोज अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.तीनो घटनाओ में संबधित थानों की पुलिस जाँच कर रही है.

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)